26

तिब्बत मुद्दे पर तिब्बत तथा चीन के सरकारी स्थिति

सिंहुआ द्वारा तिब्बत पर प्रकाशित साक्षात्कार पर टिप्पणी

प्राक्कथन

उपनिवेशवादी ताकतों ने उपनिवेशों पर शासन करने तथा उन पर अपने कब्ज़े को उचित ठहराने के लिए 'प्रचार' को अपने हाथों का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। यह उनकी सामान्य नीति रही है कि वे स्वयं को शुभचिन्तक व सभ्यता का रक्षक प्रदर्शित करने के लिंए गुलाम बनाये लोगों को घोर पिछड़ेपन से निकालने की दयापूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पिछले सचिव हू यॉबंग ने तिब्बत के प्रति चीन के दृष्टिकोण को 'शुद्ध उपनिवेशवादी' बताया। उन्होंने, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्ज़ा किये जाने के 30 वर्ष बाद, 1980 में तिब्बत में घोर गरीबी देखने के पश्चात् यह वक्तव्य दिया था।

अतः पाठक–गण चीन द्वारा तिब्बत के बारे में किये जा रहे प्रचार को इस संदर्भ में समझने का प्रयास करें। इस प्रचार में, तिब्बत को 'चीन का अभिन्न अंग' होने का दावा, तिब्बत पर 'सशस्त्र आक्रमण' को 'शान्तिपूर्ण मुक्ति' बताया जाना एवं 'सत्रह–सूत्री समझौते' को वैध समझौता कहकर थोप देना, शामिल हैं।

तिब्बत को आज मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, औद्योगिक विकास, अच्छी फसलों से परिपूर्ण सामाजिक–स्वर्ग बनाने जैसे दावे इस प्रचार में सम्मिलित है। चीन अपने बुरे कर्मों को प्रचार की एक ही धुलाई से धो देना चाहता है।

28 अप्रैल 1984 को सिंहुआ न्यूज़ एजेंसी ने, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स विभाग के प्रवक्ता से हुए लम्बे साक्षात्कार को छापा था। प्रवक्ता ने तिब्बत पर चीन के पिछले उपनिवेशी दावों को दुहराया था।

इस पुस्तिका में हमने, इन्ही दावों को बिन्दुशः आँका है ताकि तिब्बत समस्या को ठीक–ठाक जाना जा सके। यह विश्व के अपक्षपाती व ईमानदार व्यक्तियों को तिब्बत के प्रश्न और तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को समझने में सहायता प्रदान करेगी।

जुलाई 1994

तेम्पा सेरिंग
सचिव
सूचना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन
धर्मशाला – 176215
हि॰ प्र॰

प्रकाशकः सूचना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन
धर्मशाला – 176215
हिमाचल प्रदेश

हिन्दी अनुवादकर्ताः मिलिन्द्र के. ए. 'कारुणिक'

सिंहुआः– पिछले 43 वर्षों के दौरान तिब्बत में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हुए?

चीनी प्रवक्ताः–

शांतिपूर्ण तरीकों से तिब्बत को मुक्त करने के लिए 23 मई 1951 को केन्द्रीय सरकार (चीन की सरकार) और तिब्बत की स्थानीय सरकार ने सत्रह–सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।

तिब्बती वक्तव्यः–

यह तथाकथित समझौता तिब्बत एवं तिब्बती जनता पर, शस्त्रों के दबाव में चीन द्वारा जबरन थोपा गया था जबकि इससे पहले ही पी॰ एल॰ ए॰ (चीनी जनवादी मुक्ति सेना) की 40,000 टुकड़ियाँ तिब्बत के पूर्वी प्रांत की राजधानी छमदो को अपने अधिकार में ले चुकी थीं। तिब्बत के शिष्टमण्डल को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बन्दी बना लिया गया। 'समझौते' पर लगायी गई तिब्बती सरकार की नकली मुहर को बीजिंग में तैयार किया गया था।

'समझौते' पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व ही भारतीय सरकार को यह आभास हो गया था कि चीन तिब्बत पर असमान समझौता थोप देगा। भारतीय विदेश मन्त्रालय ने 26 अक्टूबर 1950 को चीनी सरकार के नाम भेजे गये अपने पत्र में इस भय को इस प्रकार व्यक्त किया थाः–

> अब जबकि चीनी सरकार ने (अपनी सेना को) तिब्बत पर आक्रमण की आज्ञा दे दी है शांतिपूर्ण समझौते की बात होना कठिन है और स्वाभाविक है कि तिब्बत को यह भय रहेगा कि ऐसे समझौते दबावपूर्ण एवं अनुचित होंगे।

तिब्बत में परम पावन दलाई लामा जी को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला। फिर भी ज्योंही उन्होंने तिब्बत को छोड़ा, उन्होंने 20 जून 1959 को औपचारिक रूप से 'समझौते' की आलोचना करते हुए कहा कि यह "तिब्बत की सरकार एवं जनता पर शस्त्रों के दबाव में लाद दिया गया है।"

माओ ज़िदोंग द्वारा 'तिब्बत में हमारे कार्य की नीति' हेतु सी॰ पी॰ सी॰ की केन्द्रीय समिति को दिये गये दिशा–निर्देशों के इन अंशों से यह स्पष्ट होता हैः–

अंशः

> ... न केवल दो सिलॉन (प्रधानमंत्री) बल्कि दलाई लामा और उनका पक्ष–दल इस समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं और अतः इसे क्रियान्वित करना नहीं

चाहते। ... अब तक हमें न तो इस समझौते को पूरी तरह लागू करने का ठोस आधार मिला है और न ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन–साधारण तथा उच्च वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ है। *[सिलेक्टिड वर्क्स आफ माओ ज़ीदोंग, संग्रह 5, फॉरेन लैंग्वेज प्रेस, पीकिंग 1977, पृ॰ 75]*

तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति, चीनी जनता के मुक्ति–उद्देश्य का महत्वपूर्ण अंग है। तब से चीन में अन्य राष्ट्रीयता के लोगों की तरह तिब्बती लोग भी समानता के अधिकार का पूरी तरह उपभोग कर रहे हैं और स्वतंत्रता तथा खुशहाली के रास्ते पर चल रहे हैं।

तिब्बत की यह 'मुक्ति' लगभग बारह लाख तिब्बतियों को मौत के घाट उतार चुकी है और छः हज़ार से अधिक तिब्बती विहारों और सांस्कृतिक केन्द्रों को नष्ट कर चुकी है। पी॰ एल॰ ए॰ के एक गोपनीय दस्तावेज़ के अनुसार केवल ल्हासा और इसके आसपास के क्षेत्रों में मार्च 1959 और अक्तूबर 1960 के बीच 87,000 तिब्बतियों की हत्या कर दी गयी। तत्पश्चात् तिब्बत को चीन का एक मात्र उपनिवेश बना दिया गया और तिब्बतियों को दूसरी श्रेणी का नागरिक।

निम्नलिखित वक्तव्य बताते हैं कि तिब्बत की यह 'मुक्ति' कितनी शांतिपूर्ण थी:–

अलैग्ज़ैण्डर सोल्ज़नित्सिन:

तिब्बत में होने वाला रक्तपात स्पष्ट करता है कि साम्यवादी चीन एक निर्दयी और अमानवीय शासक है जो साम्यवादी विश्व पेटी का सबसे अधिक दुष्ट और अमानवीय है। *[टोकियो, 9 अक्तूबर 1982]*

पंचेन लामा:

... यदि छिंगहाई प्रान्त (उत्तर–पूर्वी तिब्बत) में हुए अत्याचारों पर फिल्म बनी होती तो लोग उसे देखकर स मे का शिकार हो जाते। गोलोक क्षेत्र में बहुत से लोग मार दिये गए और उनकी लाशों को पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ी खाई में लुढ़का कर फेंक दिया गया। सैनिकों ने मृतकों के परिवारीजनों से कहा कि उन्हें खुशियाँ मनानी चाहिए क्योंकि देश–द्रोह को समाप्त किया जा चुका है। यहाँ तक कि उन्हें लाशों पर नचाया गया। इसके तुरन्त बाद ही उन्हें भी मशीन–गनों से भून दिया गया।

... आम्दो और खम् में लोगों पर अवर्णनीय अत्याचार किये गए। लोगों को दस–दस या बीस–बीस का समूह बनाकर इकट्ठा मारा गया। मैं जानता हूँ यह सब कहने से कोई लाभ नहीं है लेकिन इन कार्यों ने लोगों के हृदय में गहरे घाव छोड़े हैं। *[28 मार्च 1987 को बीजिंग में आयोजित राष्ट्रीय काँग्रेस की 'टार' स्टैंडिंग समिति की बैठक को सम्बोधन]*

पिछले 43 वर्षों में तिब्बत में तीव्र परिवर्तन आये हैं जैसे – अति प्राचीन जागीरदारी प्रथा समाप्त कर नवीनीकरण करना। बहुत से किसान मज़दूर अपने भाग्य के मालिक बन गये हैं। जबकि बहुत से तिब्बती कारीगर, शिक्षित लोग, विद्वान और कार्यालयों में काम करने वाले लोग तिब्बत को बनाने और सँवारने का कार्य अपने हाथों में लिये हुए हैं।

चीनी आक्रमण से पहले तिब्बत एक सामान्य और आत्मनिर्भर राष्ट्र था जो सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से विश्व के समृद्धशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। यद्यपि यहाँ प्रजातंत्र प्रणाली नहीं थी फिर भी इस के नागरिक पड़ोसी देशों के नागरिकों से अधिक अधिकारों का उपभोग करते थे। चार दशकों से अधिक समय से इस स्वतंत्र देश को एक विदेशी कब्ज़े (चीन द्वारा) ने केवल एक उपनिवेश बना दिया है जहाँ लोग शोषित खेतिहर मज़दूरों से अधिक कुछ भी नहीं है।

इस सन्दर्भ में हम यह पूछना चाहते हैं कि 'लाखों खेतिहर मज़दूर किस प्रकार से अपने भविष्य के मालिक' बन गये हैं जबकि इसी साक्षात्कार में तिब्बत की जनसंख्या को केवल 'बीस लाख' के लगभग बताया है। *[विशेष ज़ोर सहित]*

केन्द्रीय सरकार एवं चीन के अन्य भागों के सहयोग, समर्थन तथा तिब्बतियों के प्रयासों से तिब्बत ने विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं।

सन् 1980 में जब चीनी साम्यवादी दल के सचिव ल्हासा के भ्रमण पर गये तब उन्हें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि चीन की आर्थिक सहायता से तिब्बतियों को कोई लाभ प्राप्त हुआ हो। श्री हू ने पाया कि लोगों का जीवन–स्तर आक्रमण से पहले की तुलना में नीचे गिरा है। तिब्बत की भीषण गरीबी को देखकर उन्होंने आम लोगों के सामने इस प्रकार कहा, "यह सरासर उपनिवेशवाद है।" *[इमैंसिपेशन रीव्यू, हाँगकाँग, दिसम्बर 1980]* उल्होंने चीन के स्थानीय सेवारतों से पूछा कि क्या चीन द्वारा दी गई सहायता को "यरलुङ् च़ङपो (ब्रह्मपुत्र नदी) में फेंक दिया गया था?"

इसी प्रकार, पंचेन लामा ने अपनी अन्तिम अभिलिखित भाषण में सन् 1989 में कहा, "इस विकास के लिए तिब्बत ने खोया अधिक और पाया कम।" इस भाषण को *चाईना डेली* में इसके संवाददाता गू ज़ोंगशी ने प्रकाशित कराया था।

तिब्बत में जो कुछ भी थोड़ा विकास दिखाई पड़ता है वह मुख्यतः तिब्बत में तीव्रता से बढ़ रहे चीनी लोगों के लिए है। उदाहरण के लिए – यह सर्वविदित सत्य है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के नं॰ 3357 प्रोजेक्ट, जो ल्हासा घाटी में स्थित है, से जो लाभ तिब्बती ग्रामीणों को मिलना चाहिए था उन्हें देने के बजाय चीनी लोगों को दे दिया गया।

1993 में तिब्बत में 6,20,000 टन अनाज की उपज हुई, बड़े पालतू पशु बढ़कर 232 लाख हो गये। यहाँ नवीन उद्योग जो छोटे पैमाने से शुरू हुआ था, ने 4,700 लाख कीमत तक की वस्तुओं का निर्माण किया। इसके (तिब्बत के) ऊर्जा उत्पादन, यातायात और दूर–संचार सुविधाओं में आशातीत वृद्धि हुई है।

1960 और 1970 के दशक में भी चीनी सरकार ने फसलों के बारे में ऐसे ही बड़े आँकड़े प्रस्तुत किये थे जबकि उस समय तिब्बत में अकाल पड़ा हुआ था। उससे पहले स्वतंत्र तिब्बत के इतिहास में ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा था। जून 1989 में तियानेंमेन चौक, बीजिंग, में जब दर्शकों व टी.वी. कैमरों के सामने हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था तब चीन ने इस घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने से साफ मना कर दिया था।

खाद्यान्न उत्पादन या 'पालतू जानवरों' की संख्या में वृद्धि से तिब्बतियों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। इन वृद्धियों ने केवल चीनी लोगों को तिब्बत में जाकर बसने को बढ़ावा दिया है।

तिब्बत में औद्योगिक विकास खनन क्षेत्र में किया गया है जिससे कि तिब्बत की खनिज सम्पदा के शोषण से चीन लाभान्वित हो सके। इसके बदले में तिब्बत को आवश्यकता की सभी निर्मित वस्तुओं को चीन से मँगाना पड़ता है।

1994 की यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट में छिंगहाई और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को अन्य चीनी शासक क्षेत्र के तुलना में एच.डी.आई. स्तर के विवरण में सबसे नीचे दिखाया गया है।

केवल उन शहरी क्षेत्रों को बिजली, यातायात और दूर–संचार की सुविधाएं दी गयी हैं जहाँ चीनी लोग बसे हुए हैं। तिब्बत के अधिकतर गाँवों में विकास के अन्य पहलुओं की तो बात ही दूर है, वहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं की गयी है।

इसी बीच, तिब्बत की उत्तम पारमपरिक संस्कृति को भी फैलाया और विकसित किया गया है और

तिब्बती संस्कृति तथा धर्म को अप्रत्यक्ष एवं योजनाबद्ध ढंग से नष्ट करने का प्रयास जारी है। मई 1993 में तिब्बत गये ई.सी. प्रतिनिधि–मण्डल के

शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, जन-स्वास्थ आदि में काफी वृद्धि हुई है। तिब्बती लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। तिब्बती जनसंख्या जो 1950 में 10 लाख थी बढ़ कर 20 लाख हो गई है।

एक सदस्य ने कहा कि इस बात पर शंका है कि "धर्म को संघात्मक स्तर पर कार्य की स्वतंत्रता एवं धन दिया जाता है जिससे कि धर्म अपनी पूरी शक्ति से निखर कर तिब्बती संस्कृति तथा उसके अस्तित्व का मूल रूप से एक अंग बना रह सके।"

1980 के दशक के अंतिम भाग में पहली बार अधिकार पूर्वक तिब्बत की दौरे पर बुलाये गये विदेशी पत्रकारों में से एक सदस्य ने तिब्बत को 'सभ्यता का कब्रिस्तान' की संज्ञा दी है।

यह उल्लेखनीय है कि 1980 से (अब तक) 10,000 से अधिक बच्चे या तो स्वयं तिब्बत से भारत आ गये या उनके माँ-बाप ने उन्हें यहाँ भेज दिया ताकि वे यहाँ तिब्बती शरणार्थी समुदाय में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

चीन अपने शासन के 35 वर्षों के समय में एक भी पूर्ण शिक्षित गेशे (बौद्ध दर्शन में डाक्ट्रेट की उपाधि) नहीं बना सका। तिब्बत में आधुनिक शिक्षा में शोध करने के लिए किसी तिब्बती को शायद ही कोई अवसर मिलता है। इसके विपरीत 120,000 से कुछ अधिक की शरणार्थी जनसंख्या में से 1,000 से अधिक भिक्षु गेशे उपाधि ग्रहण कर चुके हैं और लगभग एक दर्जन तिब्बती लोग सामाजिक-आर्थिक विकास से लेकर सूक्ष्म भौतिकी तक विभिन्न विषयों पर शोध कार्य (पी.एच.डी.) कर चुके हैं।

स्वास्थ सेवाएँ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के पक्ष में जाती है जहाँ चीनी लोग बसते हैं। स्वास्थ हेतु सम्पूर्ण धन -खर्च का केवल दस प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों को जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ सेवाएँ इतनी महँगी हैं कि इनका लाभ तिब्बती नहीं ले सकते जिनकी औसत प्रति व्यक्ति आय केवल 250 युआन प्रति माह है। 1993 में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में एक बिस्तर का कम से कम खर्च 5,000 युआन प्रति माह था और प्रत्येक भ्रमण का परामर्श शुल्क 70 युआन था।

तिब्बत की जनसंख्या तीन राज्यों-आम्दो, खम् और ऊ-चाङ् में, 1959 से पहले 60 लाख थी। यदि आज जनसंख्या 20 लाख है तो इसका तात्पर्य है कि यह घट गई है, बढ़ा नहीं।

साम्यवादी दल एवं इसकी सरकार को राष्ट्रीयता एवं धार्मिक मामलों के लिए तिब्बतियों एवं तिब्बत में बसने वाले सभी राष्ट्र-प्रेमियों का पूरे हृदय से समर्थन प्राप्त है। तिब्बत के सभी भाग आज सजीवता और समृद्धि की तस्वीर बने हुए हैं।

मातृभूमि की एकता को बनाये रखने में तिब्बती लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। विभिन्न जाति के लोगों के बीच एकता बनाये रखने तथा देश की आधुनिकीकरण में भी उनका बड़ा योगदान रहा है।

भविष्य के सुधारों में समाजवादी बाज़ार पर आधारित आर्थिक तंत्र को प्रारम्भ करना शामिल है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी नीतियाँ बनाना सुचारू रखेगी जो तिब्बत की आर्थिक वृद्धि एवं तिब्बती लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने पर केन्द्रित होगी।

तिब्बत के विकास में तीव्रता लाने के लिए चीन यहाँ की विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों को उत्साहित करता रहेगा। सामान्य समृद्धि प्राप्त करने हेतु, तिब्बत का आर्थिक विकास करने के लिए, यह सुधारों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहेगा तथा तिब्बत द्वारा किये जाने वाले स्व-विकास के प्रयासों को भी अपनी सहायता प्रदान करता रहेगा।

चीनी सरकार की नीतियों को तिब्बती कर्मचारियों का भी 'पूरे हृदय से' समर्थन प्राप्त नहीं है, जन-सामान्य के समर्थन की तो बात ही दूर रही। चीन को 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' या छिंगहाई, सिचुआन, युन्नान तथा गान्सू के तिब्बती क्षेत्रों के क्षेत्रीय साम्यवादी दल के सचिव पद के लिए विश्वसनीय तिब्बती अभी भी खोजने बाकी हैं। दिसम्बर 1992 में एक उच्च-स्तरीय भाषण में चेन कुइयुआन, 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' के वर्तमान प्रथम सचिव, ने परम पावन दलाई लामा के प्रति निष्ठा दिखाये जाने पर तिब्बती कर्मचारियों की आलोचना की। केवल 1993 में चीनी शासन के विरुद्ध तिब्बत के विभिन्न भागों में जन स्तर पर 40 से अधिक प्रदर्शन हुए।

सुधार करने एवं तिब्बत की अर्थव्यवस्था को खोलने का उद्देश्य तिब्बत को चीनी निवासियों से भर देना तथा तिब्बती संस्कृति एवं उसकी राष्ट्रीय अस्मिता को समाप्त कर देना है। जब अगस्त 1993 में अर्थव्यवस्था को खोलने की पहली बार घोषणा की थी तब चीन के स्थानीय अधिकारियों ने तिब्बतियों से कहा कि वे तिब्बत के विकास के लिए चीनी 'प्रशिक्षित' कारीगरों का स्वागत करें।

इसी तरह से 'विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों' को तिब्बत के विकास के लिए उत्साहित करने के नाम पर चीनी सरकार चीनी जनसंख्या के स्थानान्तरण और प्राकृतिक सम्पदा के शोषण को सक्रियता से बढ़ा रहा है। यदि चीन वास्तव में तिब्बत के विकास में रुचि लेता है तो तिब्बतियों को स्व-निर्भर बनने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए और विकास के लिए उन्हें ही भूमिका निभाने देना चाहिए।

ई.सी. (वर्तमान ई.यू.) के बीजिंग स्थित राजदूतों के प्रतिनिधिमण्डल, जो मई 1993 में तिब्बत के दौरे पर गया था, ने इन तथ्यों की सूचनाएँ दीः-

- सरकारी सूचना और अन्य सूचनाओं, जो दूसरे स्रोतों से या प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्राप्त हुईं, में समानताएँ नहीं हैं।
- तिब्बत में रहने वाले चीनी और तिब्बती लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं है।

• सरकारी आँकड़ों में चीनी जनसंख्या (तिब्बत में) केवल तीन प्रतिशत बतायी गयी है। यह वास्तविक संख्या से बहुत कम है क्योंकि तिब्बत में बसे बहुत से चीनी लोग स्थानीय रूप से नामांकित नहीं हैं।

• बढ़ती आर्थिक क्रियाओं से तिब्बतियों के अपेक्षा हाल ही में तिब्बत आये चीनी लोगों को अधिक लाभ मिला है।

सिन्हुआः– यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है। फिर भी, दलाई लामा आज तक शरणार्थी बने हुए हैं और अपनी मातृभूमि के टुकड़े करने वाली गतिविधियों में लिप्त हैं। केन्द्रीय सरकार की दलाई लामा के सन्दर्भ में क्या नीतियाँ हैं? क्या इन नीतियों में कोई परिवर्तन हुआ है?

चीनी प्रवक्ताः–

दलाई लामा एवं उनके अनुयायियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सिद्धान्त और दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट और स्थाई हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।

जब दलाई लामा इस सच्चाई को मान लेंगे कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है और वे 'तिब्बत की स्वतंत्रता' के विचार को पूरी तरह छोड़ देंगे व मातृभूमि को तोड़ने की गतिविधियों को छोड़ देंगे और निर्वासित जीवन को जल्द से जल्द त्याग कर मातृभूमि की एकता, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास एवं तिब्बतियों की खुशहाली और समृद्धि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना योग्यदान देंगे, तो केन्द्रीय सरकार उनकी चीन वापसी का स्वागत करेगा।

तिब्बती वक्तव्यः–

तिब्बत प्रश्न पर चीनी सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। यदि चीन अपने इस दृष्टिकोण पर अडिग रहेगा तो तिब्बत समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं मिलेगा।

परम पावन दलाई लामा को यह मानने के लिए कहना कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, इसके समान है कि उनसे इतिहास को विकृत करने को कहा जाये।

हम इतिहास के इन तथ्यों का आंकलन करें:– अभी हाल तक साम्यवादी चीनी तिब्बत पर अपने दावे का आधार उस शादी को मानता था जो सातवीं शताब्दी में तिब्बत के सम्राट सोङ्चेन गाम्पो और चीनी राजकुमारी के बीच हुए थे। परन्तु वे बड़ी आसानी से यह भूल जाते हैं कि तिब्बती सम्राट के एक बड़ी दुलहिन (पत्नी), नेपाल के राजकुमारी बृकुटि देवी, भी थी। जब वे इस दावे को सच नहीं ठहरा सके तो उन्होंने अपने दावे को तेरहवें शताब्दी में तिब्बत पर मंगोल प्रभाव के स्थापित होने से जोड़ दिया। किन्तु, मंगोल एक अन्य राष्ट्र के लोग हैं और चीनियों ने उन्हें हमेशा विदेशी माना है। सन् 1911 में जब राष्ट्रवादी क्रान्ति ने चिंग वंश को शासन से हटा दिया तब सुन यात्सेन ने कहा था कि विदेशियों ने चीन का दो बार अधिग्रहण किया – पहले, युआन लोगों (मंगोल शासकों) ने और फिर चिंग (मंचू सम्राटों) ने।

किसी भी रूप से देखा जाय तो यह स्पष्ट है कि चीन

द्वारा मंगोलियाई शासकों को शासन से हटाने के 18 वर्ष पहले ही सन् 1350 में तिब्बत में मंगोल शासकों का प्रभाव समाप्त हो चुका था।

यदि तिब्बत, साम्यवादी चीन की ज़मीन का ही एक हिस्सा होता तो उसे (चीन को) तिब्बत की 'मुक्ति' के लिए उस पर 'सत्रह-सूत्री समझौता' थोपने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरे क्षेत्रों को 'मुक्त' करते समय साम्यवादी सेनाओं को इस प्रकार के समझौतों की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई।

1949 में जब नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, तब उसने अपने राष्ट्र की प्रभुता को सिद्ध करने के लिए तिब्बत के साथ हुए अपने राजनीतिक सम्बन्धों का वर्णन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेपाल के इस दलील को स्वीकार कर के तिब्बत की सम्प्रभुता को भी स्वीकार कर लिया।

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में तिब्बत के सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद में, आयरलैण्ड के प्रतिनिधि फ्रैंक ऐटकेन ने कहा:-

> हज़ारों वर्षों तक या कई हज़ार वर्षों तक तिब्बत अपने मामलों पर पूर्ण नियन्त्रण रखता था और उतना ही स्वतंत्र था जितना कि इस सभा में उपस्थित कोई भी राष्ट्र, और निजी मामलों की देख-रेख करने में वह बहुत से राष्ट्रों से हज़ार गुना अधिक स्वतंत्र। *[यू.एन.जी.ए. डॉक्यूमेंट्स ए./पी.वी. 898, 1960; ए./पी.वी. 1394, 1401, 1965]*

अंतर्राष्ट्रीय विधि-वेत्ता आयोग, जर्मन बुण्डैस्टैग एवं बहुत सी अन्य स्वतंत्र संस्थाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि चीन द्वारा कब्ज़ा किये जाने के समय तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था।

तिब्बत का मुद्दा यह नहीं है कि परम पावन दलाई लामा तिब्बत वापस लौट सकें। आज की परिस्थितियों में परम पावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी संभव नहीं। तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों को यह डर है कि वर्तमान परिस्थिति के रहते परम पावन दलाई लामा यदि तिब्बत भ्रमण के लिए भी जाते तो चीनी सत्ता उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना लेगी।

1979 में देंग ज़ियाओपिंग ने दलाई लामा के एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि से यह स्पष्ट किया कि यह बात अधिक महत्व की है कि तिब्बत चीन का एक हिस्सा है और इसी आधार पर यह परख करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत।

19 मई 1991 को सिंहुआ के एक पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते समय प्रधानमंत्री ली फंग ने केन्द्रीय सरकार की नीतियों को दुहराते हुए कहा कि केवल एक ही मौलिक सिद्धान्त है और वह यह है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है।

इस प्रश्न पर समायोजन का कोई स्थान नहीं है, ली फंग ने कहा कि केन्द्रीय सरकार दलाई लामा से सम्पर्क बनाने के लिए हमेशा तैयार है, यदि वह मातृभूमि को तोड़ने के कार्यों से अलग हो जायें और 'तिब्बत की स्वतंत्रता' की बात छोड़ दें।

उन्होंने ज़ोर देकर आगे कहा कि किसी भी बात पर वार्तालाप हो सकता है लेकिन 'तिब्बत की स्वतंत्रता' पर नहीं।

केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त नीतियाँ अटल रहेगी।

तिब्बत के मामले चीन के आन्तरिक मामले हैं। 'तिब्बत प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय बनाये जाने' के किसी भी प्रयास का, चीनी लोगों द्वारा पूरी शक्ति से विरोध किया जायेगा और उसे सफल नहीं होने दिया जायेगा।

1979 में चीनी सरकार ने परम पावन दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोन्डुब को बीजिंग में आमंत्रित किया। उस समय देंग ज़ियाओपिंग ने उनसे कहा कि (तिब्बत की) स्वतंत्रता के अतिरिक्त किसी भी प्रश्न पर विचार–विमर्श किया जा सकता है।

परम पावन दलाई लामा ने देंग ज़ियाओपिंग की इन पहलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की और कई प्रस्ताव रखे। इनमें 15 जून 1988 का स्ट्रास्बर्ग प्रस्ताव भी शामिल है जिसमें उन्होंने (दलाई लामा) ने चीन के साथ संयुक्त होने का प्रस्ताव रखा और कहा कि तिब्बत की विदेश नीति के लिए चीनी सरकार उत्तरदायी रह सकती है। इस प्रस्ताव का न केवल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने बल्कि चीन के स्वतंत्र विचारकों ने भी स्वागत किया। किन्तु चीन की सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि इसमें 'छिपे रूप में स्वतंत्रता' की ही बात कही गयी है।

तिब्बतियों का यह अधिकार है कि वे उचित कार्यवाहियों में तब तक लगे रहें जब तक कि साठ लाख तिब्बती जनता के दुःखों की समाप्ति के लिए कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हो जाता।

स्वतंत्र लोकतन्त्रात्मक देश, चीन के कठोर, शक्ति–आधारित एवं बाध्यकारी समाज से सर्वथा भिन्न होते हैं। परम पावन दलाई लामा, जिन्होंने तिब्बती लोगों में हमेशा लोकतांत्रिक विचारधारा को प्रोत्साहित किया है, इन लोगों पर कभी भी अपनी इच्छा को नहीं थोपेंगे।

अपने समझौतापूर्ण समाधान के प्रयासों को बार–बार चीनी सरकार द्वारा ठुकराये जाने पर परम पावन दलाई लामा ने बाध्य होकर ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह चीनी सरकार पर दबाव डाले ताकि वार्ता शुरू हो सके। बीते वर्षों के दौरान, विश्व की अनेक सरकारों और संसदों ने तिब्बत की न्यायोचित माँग तथा परम पावन दलाई लामा के पहलपूर्ण प्रयासों के समर्थन में कई वक्तव्य जारी किये हैं।

सिंहुआः- विदेशी तार सेवा (फॉरेन वायर सर्विस) की रिपोर्ट के अनुसार, दलाई लामा ने विभिन्न अवसरों पर यह दावा किया कि उन्होंने उन पहलपूर्ण कदमों एवं प्रस्तावों में अधिक से अधिक छूट दे दी, जो कि बातचीत हेतु वार्तालाप की परिधि में आते हैं जिनमें कि 'स्वतंत्रता' को छोड़ कर सभी प्रश्न आ जाते हैं। क्या यह सच है?

चीनी प्रवक्ताः-

यदि दलाई लामा 'तिब्बत की स्वतंत्रता' का पक्ष छोड़ दें तो यह उनकी सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन यह खेदपूर्ण है कि हमें अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है। दलाई लामा ने जब से तिब्बत छोड़ा है, उन्होंने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है और न ही उन्होंने मातृभूमि को तोड़ने की गतिविधियों को बन्द किया है।

उनके दावे या प्रस्ताव हमेशा ही 'तिब्बत की स्वतन्त्रता' पर केन्द्रित रहे हैं। हाल ही में उन्होंने तिब्बत को "बन्दी राष्ट्र" की संज्ञा दी है और कहा है: "मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि ...अन्ततः अपने बन्दी राष्ट्र को सम्मानजनक स्वतन्त्रता और शान्ति प्रदान कर सकूँगा।" [जैसा प्राप्त हुआ] उनकी तथाकथित "छूट" और कुछ नहीं है बल्कि चालों का फेर-बदल है जो अभी भी 'तिब्बत की स्वतन्त्रता' के दावे से जुड़ी हुई है।

तिब्बती वक्तव्यः-

परम पावन दलाई लामा भविष्य की ओर ज़्यादा ध्यान देकर ही अपने कार्यों द्वारा हल खोजने का प्रयत्न करते रहे हैं। उन्होंने सकारात्मक प्रस्ताओं की एक पूरी श्रृंखला की शुरूआत की, जो पुनःमैत्री और सह-संयोजकता की भावना से ओत-प्रोत है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन प्रस्तावों को निर्माणात्मक, वास्तविक और उचित ठहराया है। यह तो चीनी नेतृत्व ही है जो अपनी छाया को भूत होने की आशंका करता है।

हमने तिब्बत के भविष्यात्मक रूप के बारे में विकल्प खुले रखे हैं। लेकिन हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र था जिसे चीन ने बन्दी बना लिया है। तिब्बतवासियों को जहाँ बोलने और घूमने की स्वतन्त्रता नहीं है तो क्या यह बन्दी राष्ट्र नहीं है? हर व्यक्ति जिसका दमन किया गया है, चाहे वह चीनी लोग ही क्यों न हों, स्वतन्त्रता और शान्ति के लिए लालायित हैं।

परम पावन दलाई लामा का मध्यमार्गीय दृष्टिकोण वस्तुतः एक बड़ी 'छूट' है न कि चालों का खेल है। स्ट्रास्बर्ग प्रस्ताव एक ऐसा सकारात्मक पहल है जिसमें यह छूट बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि परम पावन दलाई लामा को तिब्बत की स्वतन्त्रता का इतिहास बदलवाने के लिए कहना तर्कसंगत नहीं है।

सिंहुआः- यह कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने दलाई लामा से वार्तालाप के लिए काफी प्रयास किये हैं। लेकिन दलाई लामा ने कई बार यह आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सरकार उनके साथ वार्ता के लिए अनिच्छुक है। वास्तविकता क्या है?

चीनी प्रवक्ताः-

दलाई लामा ने अभी तक "तिब्बत की स्वतन्त्रता" की ज़िद नहीं छोड़ी है। वार्तालाप के मार्ग में यही सबसे बड़ी रुकावट है। केन्द्रीय सरकार कठिन परिश्रम के बाद इस परिणाम पर पहुँची है कि वार्तालाप के ज़रिये दलाई लामा और उनके अनुयायी तभी अपनी मातृभूमि से जुड़ सकते हैं जब वे अपने स्वतन्त्रता के विचार को छोड़ देंगे। इससे केन्द्रीय सरकार की ईमानदारी और धैर्य प्रदर्शित होता है।

सन् 1979 से, चीनी सरकार के विभाग दलाई लामा के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सहमत हुए हैं और वास्तव में ही मातृभूमि में उनसे मुलाकात भी की तथा दलाई लामा की इच्छा के बारे में ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। उनके कुछ प्रतिनिधियों का स्वागत तो केन्द्रीय सरकार के उच्च सदस्यों ने किया है।

1989 के प्रारम्भ में, पंचेन लामा की मृत्यु हुई थी। चीनी

तिब्बती वक्तव्यः-

स्ट्रासबर्ग प्रस्ताव में परम पावन दलाई लामा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह तिब्बत की पूर्ण स्वतन्त्रता को छोड़ अन्य 'स्टेटस' के लिए वार्तालाप के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि बहुत से तिब्बतियों, जो तिब्बत में और तिब्बत से बाहर रह रहे हैं, ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। यदि चीनी सरकार ईमानदार होती तो बातचीत के रास्ते खोलने के लिए यह प्रस्ताव ही काफी होता।

यह हज़ारों बार स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस मुद्दे को सुलझाना है वह न तो परम पावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी है और न ही निर्वासित तिब्बियों की। आधारभूत मुद्दा तो तिब्बत में रह रहे साठ लाख तिब्बतियों की खुशहाली से जुड़ी है। आज, उन्हें उनके मौलिक मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है और तेज़ी से उन्हें उनके ही देश में अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तिब्बत में तिब्बतियों को ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो उनके अपने भविष्य से जुड़े हैं। चीनी सरकार को इधर-उधर की बातें करने के बजाय इन गम्भीर स्थितियों को सुधार कर अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए।

वस्तुतः 1979 से, कई विशिष्ट दल बीजिंग जा चुके हैं। चूँकि परम पावन दलाई लामा तिब्बती लोगों के निर्विरोध नेता हैं, अतः उनके द्वारा भेजे गए विशिष्ट दल इसी हैसियत से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि परम पावन दलाई लामा को चीनी सरकार के साथ अपने निजी मसले या हैसियत के बारे में विचार-विमर्श करने में कोई रुचि नहीं है।

दिवंगत पंचेन लामा के अन्तिम संस्कार पर उपस्थित होने के लिए चीनी सरकार ने उस समय आमंत्रित किया

बौद्ध संगठन के अध्यक्ष श्री झाओ पुचु ने दलाई लामा को पंचेन लामा के अन्तिम संस्कार पर उपस्थित होने के लिए उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधियों द्वारा आमन्त्रण पत्र दिया था।

इस शुद्ध धार्मिक आमन्त्रण ने दलाई लामा को 30 से अधिक वर्षों तक निष्कासन में व्यतीत करने के बाद अपने ही देश में बौद्ध लोगों से मिलने का अवसर दिया था। लेकिन दलाई लामा ने इस आमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया।

1989 के अन्तिम अर्द्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन होने के बाद से दलाई लामा ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क रोक दिए हैं।

था, जब तिब्बत में मार्शल लॉ लगा हुआ था। स्पष्ट है कि वहाँ जाने के लिए यह उचित समय नहीं था।

सन् 1982 में परम पावन दलाई लामा ने चीनी सरकार के सामने तिब्बत भ्रमण का सुझाव रखा और 1985 तक इस पर पहल की। उन्हें कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला। उन्होंने 1992 में तिब्बत भ्रमण का सुझाव दोबारा रखा, परन्तु चीनी सरकार ने एक बार पुनः इसे अस्वीकार कर दिया।

इसके विपरीत, चीनी सरकार ने ल्हासा से मार्शल लॉ हटाने से इंकार करके परम पावन दलाई लामा के वार्तालाप की पहल को किनारे कर दिया। यह सैनिक शासन (मार्शल लॉ) 1990 तक वहाँ पर लगा रहा।

इन सभी उत्तेजनाओं के होने पर भी परम पावन दलाई लामा ने अपनी शांतिपूर्ण पहल को जारी रखा है। 19 अप्रैल 1989 को एक बार पुनः परम पावन दलाई लामा ने ही नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के माध्यम से चीनी सरकार को सम्पर्क किया और यह इच्छा ज़ाहिर की कि "वार्तालाप के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुलझाने के लिए" वह हाँगकाँग में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं। तिब्बती सरकार के विश्वास के बारे में चीनी सरकार को यह भी बताया गया कि "समझौते के मार्ग की बाधाओं को परामर्श से दूर किया जा सकता है।" यह सुझाव भी अस्वीकार कर दिया गया।

तब 25 मार्च 1991 को हमने पंचेन लामा के पुनार्वतार की खोज के लिए नई दिल्ली स्थित उनके दूतावास के माध्यम से चीनी अधिकारियों से सम्पर्क किया। उस समय हम ने पंचेन लामा के पुनार्वतार की खोज के लिए प्रार्थना हेतु ल्हासा के पास की पवित्र झील पर उच्च-लामा और मठाधिकारियों के एक विशिष्ट मण्डल को भेजने की इच्छा ज़ाहिर की। यह हमारी ओर से आपस में विश्वास पैदा करने का उपाय था। तीन माह बाद हमें चीनी अधिकारियों द्वारा

इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने का उत्तर मिला।

इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा को जब यह ज्ञात हुआ कि चीनी प्रधानमंत्री ली फंग भारत यात्रा पर आ रहे हैं, उन्होंने (परम पावन दलाई लामा ने) उनसे मिलने की इच्छा का संदेश भेजा, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया।

वर्ष 1979 एवं 1992 में श्री ग्यालो थोन्डुप को दिये गये आमन्त्रणों को छोड़कर सम्पर्क एवं वार्ता की सभी पहल परम पावन दलाई लामा की ओर से हुईं। चीनियों ने उनकी सभी पहलों को न मानकर कोई भी विकल्प खुला नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि स्विटज़रलैण्ड में 18 अगस्त 1991 को स्ट्रासबर्ग प्रस्ताव को निष्क्रिय घोषित कर दिये जाने के।

उसी वर्ष, दलाई लाम ने अपनी पुस्तक 'फ्रीडम इन ऐग्ज़ाइल' में प्रकाशित मानचित्रों में चीन को कई खण्डों में बाँट दिया, जैसे तिब्बत, सिंक्यांग, मंगोलिया, मंचू आदि।

'फ्रीडम इन ऐग्जाइल' नामक पुस्तक में दिया गया मानचित्र उस क्षेत्र के ऐतिहासिक मानचित्र का पुनःप्रकाशन मात्र है।

1992 में, जब चीन की आन्तरिक दशा वैसी नहीं बनी जैसी कि दलाई लामा ने आशा की थी, तब उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क को पुनःस्थापित करने के लिए कहा। 1992 एवं 1993 में, केन्द्रीय सरकार के विभागों ने दलाई लामा के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों से दो बार मुलाकात की थी।

1992 में, दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के राजदूत ने श्री थोन्डुप से उनके दिल्ली निवास पर भेंट की और उन्हें बताया कि बीते समय में चीन 'रूढ़िवादी' रहा है लेकिन यदि तिब्बती 'वास्तविकतावादी' बन जायें तो वह भी 'नरम' होने का इच्छुक है। राजदूत ने सुझाव दिया कि वे बीजिंग जायें और चीन के उच्च–अधिकारियों से मिलें।

इसके उत्तर में, परम पावन दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार ने श्री थोन्डुप को चीन की बात सुनने के लिए बीजिंग भेजा, लेकिन कोई भी 'नरमी' दिखाने के बजाय, चीन के नेता अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने परम पावन दलाई लामा पर निराधार आरोप भी लगाये।

इसके बाद परम पावन दलाई लामा ने देंग ज़ियाओपिंग और जियांग जैमिन को विस्तृत ज्ञापन भेजा जिसमें उन्होंने इन आरोपों का खण्डन किया और सह–सहमति हेतु अपने पिछले प्रयासों का पूरा विवरण दिया। चीनी नेतृत्व को यह ज्ञापन पहुँचाने के लिए जुलाई 1993 में एक उच्च स्तरीय समिति भेजी गयी।

इस ज्ञापन में, परम पावन दलाई लामा ने चीनी सरकार से कहा कि वे तिब्बतियों के विचारणीय कोई प्रस्ताव लायें। चीनियों ने परम पावन दलाई लामा के इस प्रस्ताव को न तो स्वीकार किया और न ही अपनी ओर से कोई पहल कदमी की।

पुनः 27 अप्रैल 1994 को परम पावन दलाई लामा ने 'विदेशी सम्बन्धों की सभा' और 'विश्व सुरक्षा हेतु न्यूयार्क वकील संघ' को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे "आपसी सम्बन्धों को सुधारने के लिए (चीनी) पोलिटब्यूरो की स्टैंडिंग कमीटी के किसी भी सदस्य से किसी तीसरे देश में" मिलने के लिए तैयार हैं।

उपर्युक्त तथ्य बताते हैं कि 1979 से ही परम पावन दलाई लामा चीन के साथ सम्पर्क–सूत्र बनाने के लिए दृढ़ प्रयास करते रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने दलाई लामा के प्रतिनिधियों से 12 से अधिक वर्षों से हो रही बातचीत को लोगों के सामने नहीं रखा है। इसका यह कारण है कि केन्द्रीय सरकार ने उनसे बातचीत के दौरान यह बताया था कि इन सम्पर्कों को गुप्त रखा जायेगा और लोगों में प्रसारित नहीं किया जायेगा। दलाई लामा के प्रतिनिधियों ने भी यही वचन दिया था। हमें खेद है कि दलाई लामा की ओर से इस वचन को तोड़ दिया गया है। इसने न केवल इन सम्पर्कों को लोगों में प्रसार कर दिया है, बल्कि लोगों को भ्रमित करने के लिए तोड़–मरोड़ भी दिया है।

1982 में, जब बीजिंग में पहली खोजपूर्ण बातचीत हुई थी तब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि कार्यवाही को गोपनीय रखा जायेगा, लेकिन 8 जून को, जब तिब्बती प्रतिनिधि–मण्डल भारत पहुँचा, चीनी विदेश मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने वार्ता का एक विकृत रूप प्रचार किया और ऐसा झूठा संकेत दिया कि हमारे प्रतिनिधि–मण्डल ने तिब्बत हेतु उसी हैसियत (स्टेटस) की माँग की है, जो उस ने ताइवान को देने का वचन दिया है यदि वह (ताइवान) एकीकरण को स्वीकार करे। इस चीनी प्रवक्ता ने 18 जून 1982 के एसोशिएटिड प्रैस, समाचार प्रेषण में कहा, "ताइवान की तरह तिब्बत के लिए 'नौ सूत्रीय नीति' लागू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।"

पुनः दिसम्बर 1982 में, चीन की सरकारी साप्ताहिक पत्रिका *बीजिंग रीव्यू* ने हमारी बात–चीत की कार्यवाहियों का एक और विकृत रूप प्रकाशित किया।

तो भी, तिब्बती पक्ष गोपनीयता के अपने समझौते पर डटा रहा और प्रैस द्वारा पूछे जाने पर भी वार्ता के विषय में कुछ नहीं बताया। परिणामस्वरूप निर्वासित तिब्बत सरकार को तिब्बतियों और अपने समर्थकों से बड़ी आलोचना सुननी पड़ी। जुलाई 1982 के स्वतंत्र मासिक पत्रिका *टिबेटन रीव्यू* के सम्पादकीय में लिखा था:–

इससे पहले कि एक वक्तव्य के लिए धर्मशाला (तिब्बती

सरकार) ने क्षमा याचना प्रस्तुत की, बीजिंग ने विदेशी सम्वाददाता को बताया कि प्रतिनिधि–मण्डल ने तिब्बत के लिए उसी हैसियत (स्टेटस) की माँग की है जिसका वचन उसने ताइवान को दिया है। उन्होंने (चीन ने) इस विनती को ठुकरा दिया।

... इसलिए प्रश्न यह उठता है कि इस असाधारण प्रस्ताव से धर्मशाला क्या प्राप्त करने की आशा करता है। तिब्बत और ताइवान की स्थितियों को एक समान मानना बिल्कुल असंगत है और यदि ऐसा विचार निर्वासित तिब्बत सरकार के मन्त्रियों द्वारा निकाला जाता है तो उनकी बुद्धि पर सन्देह करने पर किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता।

1984 में, चीनी अधिकारियों ने बिना तिब्बतियों को सूचना दिये बहुत से चीनी सम्वाददाताओं (मीडिया के लोगों) को बीजिंग के वार्तालाप स्थल पर बुलाकर द्वितीय तिब्बती प्रतिनिधि–मण्डल को अचम्भित कर दिया। यह हमारी आपसी समझबूझ का उल्लंघन था और वार्तालाप का एकतरफा दृष्टिकोण प्रचार करने का उद्देश्य। यह स्वाभाविक था कि तिब्बती प्रतिनिधि–मण्डल को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बीजिंग में एक प्रैस वक्तव्य देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

1980 दशक के मध्य तक चीनी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि तिब्बतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता को आगे भी जारी रखने में उनकी रुचि नहीं रह गई है। इसने हमको इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि हम वार्ता को लोगों के सामने रखें ताकि तिब्बती लोगों एवं विश्व के लोगों के मन में कोई गलत धारणा न रह जाये।

सिंहुआः– द्विपक्षीय वार्ता का कोई परिणाम सामने क्यों नहीं आया है?

चीनी प्रवक्ताः–

इन सम्पर्कों के कोई परिणाम प्राप्त न होने और हमारे द्वारा वार्तालाप प्रारम्भ न कर पाने का कारण यह है कि दलाई लामा की ओर

तिब्बती वक्तव्यः–

हम सन् 1979 से ही बार–बार कह रहे हैं कि हम पक्षपात रहित ऐतिहासकारों और अन्तर्राष्ट्रीय वकीलों की समिति आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं जो तिब्बत और चीन के ऐतिहासिक सम्बन्धों पर अपने विचार प्रस्तुत

से इस मौलिक विषय पर कि "तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है", हमारे साथ किसी भी सामान्य समझौते पर नहीं पहुँचा है।

वे केन्द्रीय सरकार के मौलिक सिद्धान्तों को "पूर्व शर्तें व समझौते के मार्ग में बाधा" के रूप में व्यक्त करते हैं।

हम समझते हैं कि मौलिक सिद्धान्त तथाकथित पूर्व–शर्त या समझौते के मार्ग में बाधा नहीं है बल्कि सफल समझौतों की निश्चितता का आधार है।

करे यदि चीनी सरकार चीन और तिब्बत में उपलब्ध सभी सम्बन्धित प्रमाणों को स्वतंत्रापूर्वक उन्हें देखने का अवसर प्रदान करने के लिए इच्छुक हो।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, तिब्बत पर चीन के दावे का कोई भी तर्क न तो टिकाऊ है और न ही ऐतिहासिक व कानूनी तौर पर सही।

तिब्बत कभी भी "चीन का अभिन्न अंग" नहीं रहा है, इसलिए चीन के स्वार्थ अनुरूप अपने इतिहास को बदलने के लिए हमें कहना अस्वीकार्योग्य पूर्व–शर्त है और इस प्रकार से, यह वार्तालाप के मार्ग में बाधा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चीन "सफल समझौतों की निश्चितता और आधार के रूप" में चाहता है कि वह अपनी बातों पर तिब्बतियों द्वारा सच्चाई की मुहर लगवा ले, उसकी ऐसी आशा वार्तालाप के मौलिक सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

सिंहुआः– यह स्पष्ट है कि वार्तालाप शुरू न हो पाने की जिम्मेदारी दलाई लामा के पक्ष पर आती है लेकिन आज जो स्थिति है क्या उसमें इस ओर प्रगति की कोई सम्भावना है?

चीनी प्रवक्ताः–

चीन में एक कहावत है, "जब खरबूजा पक जाता है तो डाली से अलग हो जाता है, जब पानी बहता है तो नहर बन जाती है"। इसका अर्थ यह है कि जब सही परिस्थितियाँ बनती हैं तो सफलता प्राप्त हो जाती है।

प्रत्येक वस्तु के विकास के अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ

तिब्बती वक्तव्यः–

वार्ता रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह से चीनी सरकार की है। जब कभी भी तिब्बत मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आता है, चीन हमारे साथ बात–चीत करने की इच्छा की घोषणा करता है। परन्तु ये घोषणाएँ खोखली निकलती हैं जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय लोगों की राय को बहकाना और कुछ समय के लिए टालना है।

चीनी सरकार हमेशा बल और छल कपट पर निर्भर नहीं रह सकती। अन्ततः सच्चाई और न्याय की ही जीत होनी है, ठीक उसी तरह से जैसे कि पका हुआ खरबूजा डाली से अलग हो जाता है। विश्व समुदाय और चीनी लोगों द्वारा तिब्बत के प्रति बढ़ते समर्थन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है।

बातें तब तक स्पष्ट या दृष्टिगोचर नहीं होतीं जब तक कि उसका विकास एक निश्चित अवस्था तक नहीं पहुँच जाता। केन्द्रीय सरकार सच्चाई और धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखेगी।

अन्ततः दलाई लामा भी एक चीनी नागरिक हैं। हम अभी भी आशा करते हैं कि वह "तिब्बत की स्वतंत्रता" का विचार छोड़ कर निर्वासन समाप्त करके अपने बाकी जीवन काल को चीन लौट कर पूरा करेंगे।

परम पावन दलाई लामा चीन के नागरिक नहीं हैं। वे तिब्बती लोगों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते रहेंगे और केवल तभी तिब्बत लौटेंगे जब उन्हें तिब्बत–समस्या का सौहार्दपूर्ण हल मिल जायेगा।

इस प्रश्न के समाधान ढूँढने के लिए वार्तालाप ही एक मात्र सही मार्ग है। हम आशा करते हैं कि दलाई लामा स्थिति को समझेंगे, ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के साथ चलेंगे और सही निर्णय लेंगे।

पिछले पन्द्रह वर्षों में हमने तिब्बत और चीन दोनों के आपसी लाभ हेतु तिब्बत समस्या को वार्तालाप के ज़रिये हल करने के लिए कई प्रस्ताव रखे हैं। केवल वार्तालाप और तिब्बत की वास्तविकता को बारीकी और ईमानदारी से देखने की इच्छा ही टिकाऊ समाधान तक पहुँचा सकती है। हम आशा करते हैं कि चीनी सरकार हमारे प्रस्तावों का सकारात्मक उत्तर देगी और विश्वास करते हैं कि तिब्बतियों और चीनियों की यह ऐतिहासिक भूमिका एशिया और विश्व को स्थायित्व प्रदान कर सकती है।